

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.2661  
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

दूरसंचार विभाग का सुदृढीकरण

2661. श्री अमरा राम:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का दूरसंचार विभाग को सुदृढ करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या विभाग ने देश भर में 5जी सुविधा कार्यान्वित कर दी है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ड.) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ख) जी हां। सरकार ने हाल ही के वर्षों में दूरसंचार विभाग को सुदृढ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल और सुधार किए हैं, जैसे कि:

- दूरसंचार अधिनियम, 2023 की अधिसूचना और प्रवर्तन जो कि बदलते दूरसंचार परिदृश्य के अनुकूल बनाने हेतु बेहतर विनियामक प्राधिकार और लचीलेपन के साथ विभाग को सशक्त बनाता है;
- सरकार भारत को प्रौद्योगिकीय उन्नति में अग्रणी बनाने के लिए 5जी, 6जी और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु विभाग को सहायता प्रदान कर रही है;

- वैश्विक दूरसंचार पारिस्थितिकीय तंत्र में देश की स्थिति को बेहतर करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दूरसंचार अवसंरचना, प्रौद्योगिकी विनिमय, नीतिगत विकास और विनियामक संरचना की वृद्धि का संवर्द्धन के करने लिए सरकार विभाग को सुविधा प्रदान कर रही है;
- दूरसंचार क्षेत्र के प्रभावी और कुशल प्रबंधन हेतु सरकार ने विभाग के अधिकारियों को अपेक्षित और समकालीन कौशल एवं जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया;
- सरकार ने मार्गाधिकार की अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, तीव्रतर स्पेक्ट्रम आवंटन आदि जैसे प्रचालनों में लालफीताशाही को कम करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए अनेक डिजिटल पहलों का कार्यान्वयन किया है;
- सरकार साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी करने में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी को साझा करने के लिए संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ आदि जैसे अनेक उपायों के माध्यम से विभाग को प्रोत्साहित कर रही है;

(ग) से (ड) 5जी नेटवर्क को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोलआउट किया गया है और वर्तमान में देश के 783 जिलों में से 779 जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। 5जी सेवाएं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, देश में 5जी प्रौद्योगिकी के 4.6 लाख से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए जा चुके हैं।

\*\*\*\*\*